

15 सितम्बर, 2017 को

कम्पाउंड लाइवस्टॉक फीड मैनुफैक्चरर एसोसिएशन (सीएलएफएमए)

स्वर्ण जयंती समारोह 2017

मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, देवियों और सज्जनों।

आज स्वर्ण जयंती समारोह, 2017 के उद्घाटन सत्र में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं कम्पाउंड लाइवस्टॉक फीड मैनुफैक्चरर एसोसिएशन (सीएलएफएमए) भारत के आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ। यह सर्वथा उपयुक्त है कि इस संगोष्ठी के विषय “किसानों की आय को दोगुना करने में पशु कृषि की भूमिका” पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

कम्पाउंड लाइवस्टॉक फीड मैनुफैक्चरर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1967 में 233 सदस्यों के साथ हुई थी और यह भारत में संपूर्ण पशुधन, कुक्कुट और जलकृषि उद्योग का प्रतिनिधि है। यह क्षेत्र देश के कुल जीडीपी में 4% और कृषि जीडीपी में 27% का योगदान देता है। कुक्कुट क्षेत्र आम आदमी के लिए प्रोटीन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण वाहक है। इसके साथ ही यह 2 करोड़ लघु और सीमान्त किसानों को आजीविका भी प्रदान करता है। पशुओं को उनकी पोषकीय आवश्यकताओं के अनुसार संतुलित आहार के विचार को बढ़ावा देकर पशुपालन के समग्र विकास का मुख्य उद्देश्य उत्पादकता सुधार के माध्यम से उनसे अधिकतम परिणाम प्राप्त करना है।

भारतीय आहार उद्योग

आहार उद्योग चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) की 8-10% की दर से बढ़ रहा है जिसमें कुक्कुट गोपशु और जलीय आहार क्षेत्र प्रमुख वृद्धि के वाहक के रूप में उभर रहे हैं। देश में पशु प्रोटीन और डेयरी उत्पादों की मांग 2017-18 तक मिश्रित आहार उपयोग की मात्रा को 28 मिलियन टन तक बढ़ा देगी।

हमारा मिश्रित आहार उद्योग 7-8% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है और चारा उद्योग प्रत्यक्षतः पशु प्रोटीन जैसेकि दूध, अण्डे, मांस और मछली की पैदावार और उत्पादन बढ़ाने में

योगदान दे रहा है। भारत में, रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार कुल आहार की वर्तमान मांग 35 मिलिटन टन से अधिक है और यह वर्ष 2020 तक लगभग 45 मिलियन टन तक पहुंच जायेगी।

भारत में प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार के परिदृश्य में, यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि उपलब्ध नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, सभी अनिवार्य पोषकों को समाहित करने वाला मिश्रित आहार भारत में भविष्य में खली आधारित मिश्रित आहार की बढ़ती मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। इस संबंध में उद्योग अंतिम उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए गुणवत्ता मिश्रित आहार को किफायती मूल्य पर उत्पादित करने हेतु उपलब्ध संसाधनों और उत्पादन क्षमता का अत्यधिक प्रभावी और वैज्ञानिक रूप में अधिकतम उपयोग करके मिश्रित आहार की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के कार्य को तेज करना चाहिए।

सरकारी योजना

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अधीन राष्ट्रीय पशुधन मिशन को आहार एवं चारा विकास उप-मिशन के साथ कार्यान्वित कर रहा है। उप-मिशन के तहत आहार उत्पादन यूनिटों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। यह कार्यक्रम पशुधन पालकों को गुणवत्तापूर्ण आहार उपलब्ध कराने में सहायता कर रहा है जो अनंतिम रूप से पशुधन उत्पादकता को सुधरेगा। महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य पहले से ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं।

आज की इस संगोष्ठी के विषय के संदर्भ में राज्य के प्राकृतिक भौगोलिक भूभाग के कारण कृषि भूमि की कमी से किसानों को कुक्कुट, डेयरी, मात्स्यिकी, मधुमक्खी पालन तथा पशुपालन के विविध क्षेत्रों में अपार अवसर मिले हैं।

गरीबोन्मुख नीति संबंधी उपयों को समझने के लिए आपको पशुपालन सेक्टर की सामर्थ्य और कमियों की पहचान करनी होगी तथा एक व्यापक नीति तथा कार्यान्वयन योजना तैयार करने का रास्ता सुझाना होगा।

“हमें किसानों को विभिन्न क्षेत्रों जैसे बागवानी, मात्स्यिकी, फल वाले पौधों तथा पेड़ों और पशुधन पालन में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जिससे किसानों की आय आसानी से बढ़ सकेगी। किसानों के लिए जो भी किया जा रहा है उसे जानने के लिए तकनीकी ज्ञान तथा सूचना की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें वैकल्पिक कृषि कर्म के लिए सही सहायता, समर्थन तथा प्रोत्साहन मिले।

कृषि और पशुपालन एक दूसरे पर निर्भर थे तथा साथ-साथ बढ़े। छत्तीसगढ़ तथा अन्य राज्यों में देखें जहां विविधिकरण के पश्चात् किसानों की आय में कई गुना वृद्धि हुई है, तो अन्य राज्यों में भी काफी संभावनाएं हैं परन्तु हमें उन राज्यों से सीख लेनी होगी और उन प्रक्रियाओं को दोहराना होगा। एकीकृत खेती का विविधीकरण पशुपालन, मात्स्यिकी, बागवानी समेत, मधुमक्खी पालन, सब्जीय उत्पाद, कृषि वानिकी आदि प्रारंभ किया गया है। इसी तरह पूरे देश में इन्टीग्रेटेड फार्मिंग की आवश्यकता है। जिसने अनेक रूपों में किसानों की आय को बढ़ाया है। किसानों की आय को दोगुना करना समय की आवश्यकता है जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है।

“हम सभी 2022, तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कार्य कर रहे हैं। यह केवल किसानों को पशुधन पालन जैसे आय के अन्य स्रोतों के लिए प्रोत्साहित करके ही संभव है और इसके लिए देश में अपार सम्भावनाएं हैं।

कृषि सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। ऐसा करने हेतु इसने सिंचाई से लेकर फसल बीमा तक कई कार्य नीतियां तैयार की हैं।

इसे लिए नए दृष्टिकोणों तथा नवाचारों के साथ-साथ खाद्य प्रणाली से निजी सेक्टर तथा अन्य पणधारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए एकीकृत मूल्य श्रृंखलाओं की आवश्यकता होगी जो फार्म को मेज पर उपलब्ध भोजन से जोड़ेगी, स्पर्धात्मक बाजारों की आवश्यकता होगी जो किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करेगा तथा एक ऐसी सकर्मक वातावरण की आवश्यकता होगी जो नवाचार और कार्रवाई का समर्थक है।

कोई भी एक हिस्सेदार- चाहे वह सरकारी, कारपोरेट या सिविल सोसाइटी से हो- विशेषरूप से जलवायु परिवर्तन और भूमि तथा जल संसाधनों पर बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए अकेला इस काम को नहीं कर सकता, विभिन्न संगठनों तथा पणधारियों की दक्षताओं को मिलाकर तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी मंचों के माध्यम से बेहतर सहमति तैयार करके ही असली प्रभाव उत्पन्न होगा।

भारत में कई प्रमुख राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र ऐसे सार्वजनिक निजी भागीदारी मंच तैयार कर रहे हैं। विश्व आर्थिक फोरम की कृषि पहलों संबंधी नई सोच द्वारा सहायता प्राप्त करके ये राज्य स्तरीय परियोजनाएं किसानों को अधिक तथा बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए एकीकृत मूल्य श्रृंखला परियोजनाओं हेतु संयुक्त रूप से हल तैयार करने के लिए सरकारी, निजी सेक्टर, कृषि संगठनों तथा सिविल सोसाइटी को एक साथ लाते हैं।

वर्तमान में 20 से अधिक संगठन प्रसंस्करणकर्ताओं से खुदरा विक्रेता, बहुराष्ट्रीय कारपोरेशनों से स्थानीय उद्यमी तक इन राज्य भागीदारियों में लगे हुए हैं। उद्योग जगत में व्यापारिक नेतृत्व तथा सहायता से इस मॉडल को सहायता देने के लिए प्रबल वचनबद्धता है।

मुझे आमंत्रित करने तथा आहार जगत के दिग्गजों के साथ मंच सांझा करने का अवसर प्रदान के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। मैं आशा करता हूं कि यह संगोष्ठी आहार उद्योग, नीति निर्माताओं, व्यावसायिकों, प्रौद्योगिकीविदों को एक साथ लाने का अवसर प्रदान करेगी तथा इस संगोष्ठी में उपस्थित प्रतिनिधि प्रभावी विचार विमर्श करेंगे और नये विचार तथा योजनाएं तैयार होंगी जो अंततः देश के आहार जगत को लाभान्वित करेंगे। यह माना जाता है कि उद्योग जगत की कोई भी नीति किसानोन्मुख, महिला-उन्मुख तथा प्रकृति-उन्मुख होनी चाहिए। मैं यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को उनकी मूल्यवान प्रतिभागिता हेतु धन्यवाद देता हूं।

एक बार फिर से मैं इस संगोष्ठी की सफलता हेतु अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
धन्यवाद, नमस्कार।

जय हिंद।

Compound Livestock Feed Manufacturers Association (CLFMA) Golden Jubilee Celebration 2017

On 15th September 2017

Respected dignitaries on the dais , ladies and gentlemen.

I thank the organizers of CLFMA of India for inviting me at the Inaugural Session of Golden Jubilee Celebration 2017. It is appropriate that the theme of the Symposium **“Role of Animal Agriculture in Doubling the Farmer’s Income.” would be discussed.**

About Compound Livestock Feed Manufacturers Association (CLFMA)

Compound Livestock Feed Manufacturers Association of India (CLFMA) established in the year 1967 with 233 members and being the representative of the entire livestock, poultry and aquaculture industry in India. This sector contributes 4% to the total GDP of the country and contributes 27% to the agriculture GDP. The poultry sector is an important driver of ensuring the protein security for the common man. It also provides livelihood to 2 crore small and marginal farmers and. The prime objective is overall development of animal husbandry by promoting the concept of balanced feeding of animals in accordance with their nutritional requirements for deriving from them maximum output from them through productivity improvement.

Indian feed Industry

The feed industry is growing at a compound annual growth rate(CAGR) of 8-10% ,with poultry,cattle and aqua feed sectors emerging as major growth drivers.The demand of animal protein and dairy products in the country will increase the compound feed consumption volumes to 28 million tones by 2017/18.

Our Compound Feed Industry is growing at 7-8% per annum and feed industry has directly contributed towards increasing yield and production of animal proteins such as milk, eggs, meat and fish. In India, the present demand of total feeds by a conservative estimate is over 35 million tons and will touch about 45 million tons by the year 2020.

In today's Competitive business scenario, it has been scientifically proven that utilising the latest technology available, the Compound Feed containing all the essential nutrients would play a vital role in meeting the future growing demand of oil-meal based compound feed in India. In this regard, the industry has to gear up to work towards meeting the future requirements for compounded feed by making optimum use of the available resources & production capacity in the most effective & scientific manner to produce quality compound feed at an affordable price and availability to the end users.

Government Scheme

The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare under the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries is implementing National Livestock Mission with a Sub Mission on Feed and Fodder Development. Under the Sub Mission, financial assistance is being provided for the establishment of feed manufacturing units. This programme will help in providing quality feed to the livestock rearers which ultimately improves the livestock productivity. State like Maharashtra, Bihar, Gujarat, West Bengal have already taken the benefits of this scheme.

In the context of the theme of this symposium, shortage of agricultural land due to its natural geographical terrain in the State left immense opportunities and requirement for farmers to diversify in fields like poultry, dairy, fisheries, bee-keeping and animal husbandry.

In order to understand steps in pro-poor policy you have to identify strength and gaps of animal husbandry sector and propose a way forward to formulate a comprehensive policy and implementation plan, and appreciate the need for doubling farmer's income and understand vision of livestock sector and Animal Husbandry.

“We need to encourage farmers to diversify in fields like horticulture, fisheries, fruit bearing plants and trees and livestock farming, which can easily multiply farmer's income. Farmers require technical know-how and information about whatever is being done for them. We will have to ensure that they get right support, help and encouragement to go for alternative farming.

Agriculture and Animal husbandry are inter-dependent and they grow together. The states like Chhattisgarh have benefited from diversification and other states have great potential too, and we should learn from those states and adopt those processes. Similarly, integrated farming should be adopted nationwide. Its various forms have increased the farmers' income. Doubling the farmers' income is need of the hour and is the clarion call of our Prime Minister.

Notably, doubling farmer's income by 2022 is one of the key visions of Prime Minister Shri Narendra Modi.

“We all are working in order to double the income of farmers by 2022, and it is possible only through encouraging farmers to go for other sources of income like livestock farming, which has immense potential in the State.

In an effort to boost the agriculture sector, the Indian Government has set an ambitious goal to double farmer’s income by 2022. In doing so, it has unveiled strategies ranging from irrigation to crop insurance.

This will require new approaches and innovations, as well as increasing collaboration between the private sector and other stakeholders in the food system. It will require integrated value chains that connect farm to fork, competitive markets that provide better prices to farmers, and an enabling environment that supports innovation and action.

No one stakeholder – whether governmental, corporate or from civil society – can do this alone, especially given climate change and increasing pressure on land and water resources. Real impact will come from combining the competencies of diverse organizations and stakeholders and creating better alignment through Public Private Partnership platforms.

In India, several key States are developing such Public Private Partnership platforms, including in Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra. Supported by the [World Economic Forum’s New Vision for Agriculture initiative](#), these State-level projects bring together government, private sector, farmer organizations and civil society to jointly develop solutions for integrated value-chain projects that will provide farmers with more and better opportunities.

There are currently more than 20 organizations engaged in these State partnerships, ranging from processors to retailers, multinational corporations to

local enterprises. There is a strong commitment from the Industry to support this model through business leadership and support.

I thank the organizers for inviting me and providing me an opportunity to share the dais with luminaries of the feed industry. I hope that this Symposium will bring feed industry, policy makers, professionals, technologists and delegates present in the symposium will have effective deliberations and come out with new ideas and thoughts which will eventually benefit the feed industry in the country.. It is believe that any policy in industry has to be pro farmer, pro women and pro nature. I thank each and everyone present here for their valued participation.

Once again I express my best wishes to all for the success of the Symposium.

Thank you. Namaskar.

Jai Hind

प्रेस विज्ञप्ति

माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने 15 सितम्बर, 2017 को मिश्रित पशुधन चारा उत्पादन संघ -सीएलएफएमए, द्वारा मुंबई में आयोजित संगोष्ठी- किसानों की आय को दोगुना करने में पशु कृषि की भूमिका” में लोगों को सम्बोधित किया।

- हम सभी 2022, तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कार्य कर रहे हैं। यह केवल किसानों को पशुधन पालन जैसे आय के अन्य स्रोतों के लिए प्रोत्साहित करके ही संभव है और महाराष्ट्र में इसकी अपार सम्भावनाएं हैं।
- गरीबोन्मुख नीति संबंधी उपयों को समझने के लिए पशुपालन सेक्टर की सामर्थ्य और कमियों की पहचान करनी होगी।

सहार, मुंबई: माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि “हम सभी 2022, तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कार्य कर रहे हैं। यह केवल किसानों को पशुधन पालन जैसे आय के अन्य स्रोतों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करके ही संभव है और इसके लिए महाराष्ट्र में अपार सम्भावनाएं हैं। कृषि मंत्री ने यह बात आज मुंबई में आयोजित “किसानों की आय को दोगुना करने में पशु कृषि की भूमिका” संगोष्ठी में कही। यह संगोष्ठी, होटल मैरियट, सहार, मुंबई में आयोजित की गयी थी। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडनविस, तेलंगाना के वित्त मंत्री श्री ईटाला रजिन्दर और महाराष्ट्र के एएचडी&एफ मंत्री श्री महादेव जगन्नाथ जंकार भी उपस्थित थे।

कृषि मंत्री ने कहा कि इस संगोष्ठी के विषय के संदर्भ में राज्य के प्राकृतिक भौगोलिक भूभाग के कारण कृषि भूमि की कमी से किसानों को कुक्कुट, डेयरी, मात्स्यिकी, मधुमक्खी पालन तथा पशुपालन के विविध क्षेत्रों में अपार अवसर मिले हैं। उन्होंने कहा कि गरीबोन्मुख नीति संबंधी उपयों को समझने के लिए पशुपालन सेक्टर की सामर्थ्य और कमियों की पहचान करनी होगी तथा एक व्यापक नीति तथा कार्यान्वयन योजना तैयार करने का रास्ता सुझाना होगा और साथ ही किसानों की आय को दोगुना करने की आवश्यकता की सराहना करनी होगी तथा पशुधन सेक्टर और पशुपालन की विज्ञान को समझना होगा।

कृषि मंत्री ने कहा कि हमें किसानों को विभिन्न क्षेत्रों जैसे बागवानी, मात्स्यिकी, फल वाले पौधों तथा पेड़ों और पशुधन पालन में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है, जिससे किसानों की आय आसानी से बढ़ सकेगी। किसानों के लिए जो भी किया जा रहा है उसे जानने के लिए तकनीकी ज्ञान तथा सूचना की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें वैकल्पिक कृषि कर्म के लिए सही सहायता, समर्थन तथा प्रोत्साहन मिले।

उन्होंने कहा कि कृषि और पशुपालन एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा साथ-साथ आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ तथा अन्य राज्यों में देखें जहां विविधिकरण के पश्चात् किसानों की आय में कई गुना वृद्धि हुई है, तो अन्य राज्यों में भी काफी संभावनाएं हैं परन्तु हमें उन राज्यों से सीख लेनी होगी और उन प्रक्रियाओं को दोहराना होगा। विशेष रूप से 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विजन का एक प्रमुख भाग है।

कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसके लिए इसने सिंचाई से लेकर फसल बीमा तक कई कार्य नीतियां तैयार की हैं। परन्तु यदि खाद्य मूल्य श्रृंखला के रूप में कोई परिवर्तन लाना है तो इसे उत्पादन उन्मुख प्रणाली से मांग-उन्मुख प्रणाली में बदलना होगा जो तेजी से उपभोक्तों को उत्पादों से जोड़ती है।

उन्होंने कहा कि इसके लिए नए दृष्टिकोणों तथा नवाचारों के साथ-साथ खाद्य प्रणाली से निजी सेक्टर तथा अन्य पणधारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए एकीकृत मूल्य श्रृंखलाओं की आवश्यकता होगी जो फार्म को मेज पर उपलब्ध भोजन से जोड़ेगी, स्पर्धात्मक बाजारों की आवश्यकता होगी जो किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करेगा तथा एक ऐसी सकर्मक वातावरण की आवश्यकता होगी जो नवाचार और कार्रवाई का समर्थक है।

उन्होंने कहा कि कोई भी एक हिस्सेदार- चाहे वह सरकारी, कारपोरेट या सिविल सोसाइटी से हो- विशेषरूप से जलवायु परिवर्तन और भूमि तथा जल संसाधनों पर बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए अकेला इस काम को नहीं कर सकता, विभिन्न संगठनों तथा पणधारियों की दक्षताओं को मिलाकर तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी मंचों के माध्यम से बेहतर सहमति तैयार करके ही असली प्रभाव उत्पन्न होगा।

मिश्रित पशुधन चारा उत्पादन संघ के बारे में (सीएलएफएमए)

भारतीय मिश्रित पशुधन चारा उत्पादन संघ (सीएलएफएमए) की स्थापना वर्ष 1967 में 233 सदस्यों के साथ हुई थी और यह भारत में संपूर्ण पशुधन, कुक्कुट और जलकृषि उद्योग का प्रतिनिधि है। यह क्षेत्र देश के कुल जीडीपी में 4% और कृषि जीडीपी में 27% का योगदान देता है। कुक्कुट क्षेत्र आम आदमी के लिए प्रोटीन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण वाहक है। इसके साथ ही यह 2 करोड़ लघु और सीमान्त किसानों को आजीविका भी प्रदान करता है। पशुओं को उनकी पोषकीय आवश्यकताओं के अनुसार संतुलित आहार के विचार को बढ़ावा देकर पशुपालन के समग्र विकास का मुख्य उद्देश्य उत्पादकता सुधार के माध्यम से उनसे अधिकतम परिणाम प्राप्त करना है।

15.09.2017

Press Note

Hon'ble Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shri Radha Mohan Singh addressed a gathering at a seminar on Role of Animal Husbandry in Doubling Farmers' Income, organised by Compound Livestock Feed Manufacturers Association (CLFMA) on September 15, 2017, in Mumbai.

- All of us are working to double farmers' income by 2022, and this can be accomplished only by encouraging farmers to adopt other sources of income like Animal Husbandry, which has immense potential in the state of Maharashtra.
- Identifying strengths and weaknesses of Animal Husbandry sector is important to understand pro-poor policy steps.

Sahar, Mumbai: Hon'ble Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shri Radha Mohan Singh said that we are working to double farmers' income by 2022, and this can be accomplished only by encouraging farmers to adopt other sources of income like Animal Husbandry, which has immense potential in the state of Maharashtra. He was speaking at a seminar on Role of Animal Husbandry in Doubling Farmer's Income, organised by Compound Livestock Feed Manufacturers Association (CLFMA) at Hotel JW Marriot, Mumbai. Maharashtra CM Shri *Devendra Fadnavis*, Finance Minister Telangana Shri Etela Rajender and Maharashtra AHD&F Minister Shri Mahadev Jagannath Jankar were also present at the event.

The Agriculture Minister said that in the context of the topic of this seminar, in the absence of sufficient agricultural lands due to the natural geographical terrain of the state, farmers got many opportunities in other fields like poultry, dairy, fishery, bee keeping and Animal Husbandry. Identifying strengths and weaknesses of Animal Husbandry sector is important to understand pro-poor policy steps and drawing up a comprehensive policy and its implementation plan. We should appreciate the need to double the farmers' income and understand the vision of livestock and Animal Husbandry sector.

He said that we have to encourage farmers to diversify in allied sectors like horticulture, fisheries and livestock farming as it can help them in increasing their income. In addition, farmers should be technologically sound to understand the reforms introduced for their welfare. We also have to provide support to encourage them to adopt alternative farming.

The Minister said that agriculture and Animal Husbandry are interdependent and they grow together. The states like Chhattisgarh have benefited from diversification and other states have great potential too, and we should learn from those states and adopt their processes. It is the dream of our Prime Minister Shri Narendra Modi to double the farmers' income by 2022.

In order to promote agriculture sector, the Government has set up an ambitious target of doubling the farmers' income by 2022. Several policies ranging from irrigation to crop insurance

have been devised to accomplish the goal. However, if we have to change the food value chain, then we need to shift from production-oriented system to demand-oriented system, which quickly connects consumers with products.

He said to accomplish this goal, new approach and innovation would be necessary. In addition, food value chain will have to enhance the cooperation between private sector and other stakeholders. To make it work, an integrated value chain linking farm to the table is needed; Competitive markets is required to provide better value to the farmers; and a transitive environment to support innovation and action.

He said considering climate change and increasing pressure on land and water resources, it is not possible for a single stakeholder – be it governmental, corporate or from civil society – to accomplish it alone. We can make a difference by combining the competencies of diverse organizations and stakeholders and creating a better alignment through public private partnership platforms.

Compound Livestock Feed Manufacturers Association (CLFMA)

Established in 1977 with 233 members, Compound Livestock Feed Manufacturers Association of India (CLFMA) represents the entire livestock, poultry and aquaculture industry in the country. This sector contributes 4% to the total GDP of the country and contributes 27% to the agriculture GDP. The poultry sector is an important driver of ensuring the protein security for the common man. It also provides livelihood to 2 crore small and marginal farmers. The prime objective is overall development of Animal Husbandry by promoting balanced feeding of animals in accordance with their nutritional requirements for deriving the maximum output from them through productivity improvement.
